RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 26 JUNE TO 2 JULY 2024 प्रति बुधवार वर्ष 09 अंक 40 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

बजट से उम्मीदः इस बार बजट में नए टैक्स रिजाइम वालों के लिए बढ़ सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन

Page 3

व्हिस्की, ब्रांडी, वोदका, रम... दुनिया को लगा भारतीय शराब का चस्का, बाजार में आते ही मच रही लूट

Page 4

मोदी 3.0 के पहले बजट में रोबोट टैक्स! निर्मला सीतारमण को एक्सपर्ट्स का प्रपोजल

Page 5

editorial

आतंक का विरोध जरूरी

आतंकवाद विश्व के समक्ष एक बड़ी चुनौती है. इससे निपटने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की एक श्यक लेकि इससे निपटने के लिए व्यापक और सरगनाओं को शरण देते हैं, तो कुछ ऐसे देश भी हैं, जो अपनी विदेश एवं रक्षा नीति के एक तत्व के रूप में आतंक का इस्तेमाल करते हैं. फिर भी ऐसे देश दूसरों को लोकतंत्र, शांति और मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने की चेष्टा करते हैं. कनाडा के ऐसे रवैये से क्षुब्ध होकर भारत ने कहा है कि वहां हो रहा आतंकवाद का निरंतर महिमामंडन निंदनीय है. साल 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को बम विस्फोट से तबाह करने की घटना के 39 वर्ष होने के अवसर पर कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने यह भी कहा है कि कनाडा में आतंक की प्रशंसा करने वाले आयोजनों को अनुमति देना दुर्भाग्यपूर्ण है. शांति के पैरोकार सभी देशों और लोगों को ऐसे कृत्यों की भर्त्सना करनी चाहिए. कनिष्क बम कांड कनाडा में बसे खालिस्तानी आतंकियों की करतूत थी, जिसमें विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गये थे. मृतकों में 86 बच्चे भी थे. आज भी कनाडा, अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी देशों में पनाह लिये आतंकी एवं अलगाववादी ऐसे हमलों की सराहना करते हैं तथा भारत विरोधी कार्यक्रम करते रहते हैं. इतना ही नहीं, चार दशक बाद भी इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कनाडा सजा नहीं दे सका है. शांति एवं लोकतंत्र का समर्थक कहने वाले देश कनाडा की संसद में कुछ दिन पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी गयी, जिसकी हत्या पिछले साल जून में हुई थी. इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारत ने कनाडा से कहा है कि जो लोग भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और हिंसा की वकालत कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. आज विश्व में भारतीय मूल के लोग सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हैं. जिस भी देश में वे हैं, वहां के विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं. इस कारण हर जगह उनका बड़ा सम्मान भी है. लेकिन उन देशों में कुछ भारत-विरोधी तत्व समुदाय की एकता और भाईचारे को तोड़ने में लगे हैं. ऐसे गिरोह अमेरिका और कनाडा से लेकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत अनेक देशों में सक्रिय हैं. इन देशों की सरकारें भारत के लगातार अनुरोध के बाद भी रोक नहीं रही हैं. भारत को धमकी देने की प्रवृत्ति और भारतीयों पर हमलों की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राजनीतिक लाभ के हिसाब से आतंक, अतिवाद और हिंसा को नहीं देखा जाना चाहिए तथा दूसरे देशों की एकता एवं अखंडता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए.

GST काउंसिल की पहली बैठक में कई बड़े फैसले

दूध के डिब्बों पर 12% टैक्स, रेलवे की कई सर्विस को जीएसटी से छूट

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की पहली बैठक 22 जून को हुई। आम चुनाव में जीत के बाद मोदी 3.0 सरकार में जीएसटी की इस पहली बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई मुद्दे थे। हालांकि समय की कमी के कारण कुछ पर चर्चा नहीं हो सकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी एजेंडे पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे भारत में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है। बताया कि इससे फर्जी बिलों के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी।

जीएसटी परिषद की पहली बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए 30-11-2021 तक दायर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (4) के तहत किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 2011 से 2021 मानी जा सकती है। इसलिए 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी रूप से समान आवश्यक संशोधन के

लिए, परिषद ने एक सिफारिश की है।' नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक थी।

रेलवे की सेवाओं को जीएसटी से छूट

सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 1 करोड़ रुपये, तथा उच्चतम न्यायालयों के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है। वहीं रेलवे सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे प्लेटफॉर्म टिकट, बैटरी चालित कार सेवाओं आदि को जीएसटी से छूट दी गई है।

दंड पर ब्याज माफ

जीएसटी पंजीकरण की सुविधा के लिए, जीएसटी परिषद के अनुसार, देश भर में नए पंजीकरण के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है। परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए मांग नोटिस पर ब्याज और दंड माफ करने का निर्णय लिया।

दूध के डिब्बों पर 12% जीएसटी दर

परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। जिसका मतलब है कि दूध की पैकिंग के लिए स्टील, लोहा, एल्युमीनियम, जो भी चीज का उपयोग में हो, उस पर इसी दर से जीएसटी का भुगतान होगा। उनका एक मानक आकार होता है, जिससे यह निर्धारित होगा कि दूध का डिब्बा क्या है और क्या नहीं। परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स और केस पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। इससे हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को विशेष रूप से मदद मिलेगी।

वहीं परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स और नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के मामलों पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। वित्त मंत्री ने कहा कि 'इससे हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को विशेष रूप से मदद मिलेगी।

जीएसटी कम करने का अनुरोध

वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने यह भी स्पष्ट किया और सिफारिश की कि स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12इ जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उर्वरकों पर जीएसटी कम करने का अनुरोध जीओएम को भेजा है। वर्तमान में, 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है और यह क्षेत्र लंबे समय से उर्वरकों पर जीएसटी से छूट की मांग कर रहा है। सितंबर 2021 और जून 2022 में हुई अपनी 45वीं और 47वीं बैठकों में जीएसटी परिषद ने रासायनिक उर्वरकों पर कर की दर को और कम करने की संभावना पर चर्चा की। हालांकि, परिषद ने दरों में बदलाव का सुझाव नहीं दिया।

जितना विदेशी मुद्रा भंडार, उससे ज्यादा हो गया कर्जा

663 अरब डॉलर का आंकड़ा हुआ पार

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले एक साल में भारत का विदेशी कर्ज बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, यह आंकड़ा मार्च, 2024 के अंत तक 39.7 अरब डॉलर बढ़कर 663.8 अरब डॉलर हो गया है। यह कर्जा अब देश के विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जून को समाप्त सप्ताह में 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर था। जबकि भारत का विदेशी कर्जा बढ़कर 663.8 अरब डॉलर हो चुका है। यह विदेशी मुद्रा भंडार के मुकाबले करीब 10.91 अरब डॉलर ज्यादा है। अगर मूल्यांकन प्रभाव को छोड़ दिया जाए, तो विदेशी कर्जा 39.7 बिलियन डॉलर के बजाय 48.4 बिलियन डॉलर बढ़ गया होगा। हालांकि इस बढ़त के बावजूद देश की जीडीपी में विदेशी कर्ज की हिस्सेदारी घटकर 18.7 फीसदी रह गई है।मार्च, 2023 के अंत तक यह आंकड़ा करीब 19 फीसदी था। इस अनुपात में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, सरकार का बाह्य ऋण जीडीपी का 4.2 प्रतिशत था, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र का बाह्य ऋण 14.5 प्रतिशत था।

आरबीआई ने कही ये बात

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि 'अमेरिकी डॉलर में लिया गया कर्ज भारत के कुल विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा है, मार्च 2024 के अंत में इसकी हिस्सेदारी 53.8 फीसदी थी। इसके बाद भारतीय रुपये (31.5 फीसदी), येन (5.8 फीसदी), एसडीआर (5.4 फीसदी) और यूरो (2.8 फीसदी) का स्थान आता है।' इसके अलावा, कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा लोन का है, जिसकी हिस्सेदारी 33.4 फीसदी है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

Budget 2024: क्या सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ेगी?

नई दिल्ली। एजेंसी

हर साल यूनियन बजट से पहले जिन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80 सी शामिल है। इसकी बड़ी वजह यह है कि करोड़ों टैक्सपेयर्स इस सेक्शन का फायदा उठाते हैं। इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने से पहले भी सेक्शन 80सी काफी चर्चा थी। हालांकि, दिसंबर 2023 में ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया था कि अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि बड़े ऐलान के लिए जुलाई में आने वाले फुल बजट का इंतजार करना होगा।

लोगों की सेविंग्स बढ़ाने में मिलेगी मदद

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने पेश होने वाले बजट में सेक्शन 80 सी की लिमिट बढ़ाने की ऐलान कर सकती हैं। इसकी कई वजहें हैं। पिछले कुछ सालों में रिटेल इनफ्लेशन खासकर फूड इनफ्लेशन तेजी से बढ़ा है। इससे लोगों का रोजमर्रा की चीजों पर खर्च बढ़ा है। इसका सीधा असर उनकी सेविंग्स पर पड़ा है। इनकम बढ़ने के बावजूद कई लोगों की सेविंग्स नहीं बढ़ी है। अगर सरकार सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाती है तो लोगों को सेविंग्स बढ़ाने का मौका मिलेगा।

नई रीजीम में टैक्सपेयर्स की कम दिलचस्पी

सरकार ने बजट 2023 में इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई ऐलान किए थे। इसके बावजूद नई टैक्स रीजीम में लोगों की दिलचस्पी नहीं बढ़ी है। पिछले साल अगस्त में आए ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म क्लियर के सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे ने बताया है कि अब भी 85 फीसदी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि बजट 2020 में ऐलान के 4 साल बाद भी नई रीजीम में लोगों की दिलचस्पी नहीं बढ़ी है।

इसलिए सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने से करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।

अभी सालाना 1.5 लाख रुपये की लिमिट

इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम में सेक्शन 80सी का फायदा मिलता है। अभी 80सी की लिमिट सालाना 1.5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स (ELSS), PPF, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन भी इसी सेक्शन के तहत मिलता है। उपर्युक्त इंस्ट्रूमेंट्स में एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

2014 से नहीं बढ़ाई गई है लिमिट

सेक्शन 80सी की लिमिट 2014 से नहीं बढ़ाई गई है। इस तरह बीते 10 साल से यह लिमिट 1.5 लाख रुपये बनी हुई है। इस बीच लोगों की इनकम काफी बढ़ी है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को रुपये की एजस्टेड वैल्यू को देखते हुए सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने की जरूरत है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये करना चाहिए। इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी। फूड इनफ्लेशन और पेट्रोल की ऊंची कीमतों के चलते उसकी सेविंग्स नहीं बढ़ पा रही है।

प्लैटफॉर्म टिकट, हॉस्टल... जानें अब किस-किस पर नहीं लगेगा जीएसटी

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई GST काउंसिल में कई सिफारिशें आईं। इसमें सबसे बड़ी सिफारिश जो है, वह यह कि भारतीय रेलवे की ओर से आम लोगों को दी जाने वाली सेवाओं को उदऊ के दायरे से बाहर रखा जाए। इसमें प्लैटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम की सुविधा, बैटरी चालित कार जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इंट्रा-रेलवे सप्लाई को भी GST से छूट दी जा रही है। जाहिर है कि इससे ये सेवाएं सस्ती होंगी। मीटिंग के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मीटिंग में व्यापार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इससे व्यापारियों, MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा, काउंसिल ने उदऊ एक्ट की सेक्शन 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं। इसी के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।

सोलर कुकर, मिल्क कैन और कार्टन बॉक्स पर 12% टैक्स

GST काउंसिल ने दूध के कैन (Milk cans) पर 12% के दर से टैक्स लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12% की दर निर्धारित की है। सभी सोलर कुकर पर भी 12% GST दर लागू होगी। साथ ही फायर स्प्रिंकलर समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर भी 12% GST की दर लागू होगी।

हॉस्टल सेवाओं के लिए 20 हजार रुपये तक छूट

शैक्षणिक संस्थानों के बाहर हॉस्टल सेवाओं के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति माह तक छूट दी गई है। यह छूट छात्रों या कामकाजी वर्ग के लिए है और कम से कम 90 दिनों तक रहने पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।

'पेट्रोल-डीज़ल को GST के दायरे में लाने का इरादा'

निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार का इरादा पेट्रोल, डीजल को उदऊ के दायरे में लाने का है। इसके लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। राज्यों को इसमें शामिल होकर फ्यूल्स पर उदऊ दर तय करने की जरूरत है। दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन हुआ है, जो अगस्त में GST परिषद को रिपोर्ट देगा। GST काउंसिल की अगली बैठक अब अगस्त में होगी, जिसमें बाकी बचे अजेंडे पर चर्चा होगी।

अपील के लिए मौद्रिक सीमा तय की

सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए उदऊ काउंसिल ने विभिन्न अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष टैक्स विभाग की ओर से अपील दायर करने के लिए एक मौद्रिक सीमा (मॉनेटरी लिमिट) तय की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख रुपये, हाई कोर्ट के लिए एक करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए दो करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा तय करने की सिफारिश की गई है। यह भी सिफारिश की है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 25 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये की जाए।

शेयर बाजार में फिर टूटे रिकॉर्ड, रिलायंस और बैंकिंग शेयर चमके

निवेशकों ने 1.21 लाख करोड़ कमाए

शेयर बाजार में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बुधवार 25 जून को भी जारी रहा। सेंसेक्स जहां 600 अंकों से अधिक की उछाल के साथ नई उंचाई पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 23,850 के पार चला गया। इसके चलते आज शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 1.21 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। सेंसेक्स और निफ्टी में सबसे अधिक वेटेज रखने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब 4 फीसदी की उछाल के साथ अपने 52-वीक हाई के करीब पहुंच गए। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में तेजी से भी इंडेक्स को सपोर्ट मिला। हालांकि दूसरी ओर मिडकैप शेयरों में मुनाफावसूली आज भी जारी रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स 0.29 फीसदी गिरकर बंद हुए। दूसरी ओर स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.15 फीसदी की तेजी रही। कारोबार के अंत में, बीएसई सेंसेक्स 620.73 अंक या 0.80ु की तेजी के साथ 78.674.25 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने 78,759.40 का नया उच्च स्तर छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 120.60 अंक या 0.51ु बढ़कर 23,841.90 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने भी 23,889.90 का नया आलटाइम हाई बनाया।

निवेशकों ने रुपए 1.21 लाख करोड़ कमाए

बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 25 जून को बढ़कर 436.97 लाख करोड़ रुपये पहुंच आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 24 जून को 435.76 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.21 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.21 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

सेंसेक्स के 5 सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर

बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों में सबसे अधिक 3.87 फीसदी की तेजी रही। इसके बाद भारती एयरटेल (Bharti Airtel) अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement), सन फार्मा (Sun Pharma) और अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports) के शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखी गई और ये 1.28% से लेकर 3.31 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स के 5 सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर

वहीं सेंसेक्स के बाकी 12 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) का शेयर 1.89 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। इसके अलावा टाटा स्टील (Tata Steel), टेक महिंद्रा (Tech Mahindra), जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel) और टाइटन (Titan) के शेयर क्रमशः 0.98% से लेकर 1.59% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए।

लागू होने जा रहा टेलीकॉम एक्ट, जान लीजिए क्या-क्या बदल रहा

नई दिल्ली। एजेंसी

नया दूरसंचार अधिनियम 2023 आज यानी 26 जून से लागू हो रहा है। आज से अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हो जाएंगे। यह नया टेलीकॉम एक्ट भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम (1933) जैसे मौजूदा कानून को खत्म कर देगा। नए दूरसंचार कानून में सरकार को आपातकाल के समय किसी भी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण लेने की अनुमति होगी। सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के लिए भी दूरसंचार सेवाओं का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके अलावा इस एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं।

ये हैं टेलीकॉम एक्ट की खास बातें

दूरसंचार विधेयक 2023 की खास बातों की बात करें तो इसमें कई सख्त प्रावधान हैं। इस एक्ट में फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा उसके बाद ही सिम जारी होगा। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर तीन साल की जेल और जुर्माना लगेगा।

एक्ट में हैं सख्त प्रावधान

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्स से ही लेने होंगे। प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए यूजर्स की पूर्व सहमति जरूरी होगी। इसी के साथ बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डाटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रेकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए भी 3 साल की कड़ी सजा और 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

डीएनडी का ऑप्शन

टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स को ऊ्ऊ (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। यूजर्स अब बार-बार डिस्टर्ब करने वाले फोन कॉल्स की शिकायत भी कर पाएंगे। वहीं इस नियम का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी।

बजट से उम्मीदः इस बार बजट में नए टैक्स रिजाइम वालों के लिए बढ़ सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार बन चुकी है। मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद अब सबकी निगाहें बजट पर हैं। अगले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। लोगों को हर बार की तरह इस बार भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बार नए टैक्स नियमों के लिए सरकार मानक कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें छूट वाली पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पूंजीगत लाभ तंत्र में बड़े बदलाव करने की संभावना नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आयकर विभाग समीक्षा की मांग कर रहा है। विभिन्न एसेट वर्गों में होल्डिंग अवधि को एक समान करने के सुझाव दिए गए हैं, लेकिन सरकार कम से कम फिलहाल इस प्रणाली में बदलाव करने के लिए इच्छुक नहीं है।

कई मुद्दों का किया जा रहा मूल्यांकन

बजट की रूपरेखा पर चर्चा अभी शुरू हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक परामर्श कर रही हैं, लेकिन अधिकांश कवायद फिलहाल वित्त मंत्रालय तक ही सीमित है। कई मुद्दों पर आंतरिक मूल्यांकन किया जा रहा है, जिनमें से कुछ पर सरकार के अन्य विभागों के साथ चर्चा की जाएगी, उसके बाद वित्त मंत्रालय पीएमओ से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा।

क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

जानकारी के मुताबिक, सरकार के अधिकांश भाग करदाताओं को रियायतें देने के पक्ष में हैं। विशेष रूप से मध्यम वर्ग को, जो मोदी सरकार का समर्थक रहा है, लेकिन वह अपने द्वारा चुकाए गए टैक्स के बदले मिलने वाले लाभ के बारे में लगातार सवाल उठा रहा है, चाहे वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा।

ऐसा रहा था पिछला बजट

साल 2023 के बजट में, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी करदाताओं और पेंशन पाने वालों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती की शुरुआत की थी, जो डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गया, जब तक कि आपने इसे चुनने का विकल्प नहीं चुना। साथ ही, नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये से अधिक नहीं की कर योग्य आय के लिए धारा 87ए के तहत छूट बढ़ा दी गई, जिससे इस स्तर (कर योग्य आय) तक की आय वालों को नई व्यवस्था के तहत कोई कर नहीं देना पड़ा। नई व्यवस्था के तहत सबसे अधिक अधिभार भी हटा दिया गया।

दिए हैं ये सुझाव

मौजूदा समय में, 3 लाख रुपये से ज्यादा की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता है और उद्योग जगत के नेताओं की ओर से सुझाव दिए गए हैं कि खपत को बढ़ावा देने के लिए उच्च ब्रैकेट में दरों में बदलाव किया जाए। उच्च मानक कटौती से सभी वेतनभोगी करदाताओं को लाभ होगा, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भी शामिल हैं, हालांकि इससे कुछ राजस्व हानि होगी।

जितना विदेशी मुद्रा भंडार, उससे ज्यादा हो गया कर्जा

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके बाद मुद्रा और जमा (23.3 फीसदी), व्यापारिक ऋण और अग्रिम (17.9 फीसदी) और ऋण पत्र (17.3 फीसदी) का स्थान आता है।

एक साल में इतना बढ़ा कर्जा

वहीं, एक साल से अधिक की अवधि वाले दीर्घकालिक कर्ज में 45.6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। यह मार्च 2024 के अंत में 541.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि, एक साल से कम अवधि वाले अल्पकालिक कर्ज का अनुपात कुल विदेशी कर्ज में कम हुआ है। यह मार्च 2024 के अंत में 18.5 फीसदी था, जबकि मार्च 2023 के अंत में 20.6 फीसदी था। इसी तरह, विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात में अल्पकालिक कर्ज का अनुपात भी कम होकर मार्च 2024 के अंत में 19.0 फीसदी (मार्च 2023 के अंत में 22.2 फीसदी) पर पहुंच गया है।

इकोनॉमी के लिए आई गुड न्यूज

जनवरी-मार्च तिमाही में सरप्लस रहा देश का चालू खाता, देखिए ये आंकड़े

नई दिल्ली। एजेंसी

अक्टूबर-दिसंबर, 2023 की तिमाही में चालू खाते में 8.7 अरब डॉलर का घाटा हुआ था, जो जीडीपी का एक प्रतिशत था। मार्च तिमाही का आंकड़ा आने के साथ ही 2023-24 के समूचे वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा 23.2 अरब डॉलर पर आ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। देश के चालू खाते में इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में सरप्लस की स्थिति रही और यह 5.7 अरब डॉलर रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.6 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरबीआई ने भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट पर जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में चालू खाते में 1.3 अरब डॉलर के घाटे की स्थिति थी, जो जीडीपी का 0.2 प्रतिशत थी।

इससे पहले रहा घाटा

अक्टूबर-दिसंबर, 2023 की तिमाही में चालू खाते में 8.7 अरब डॉलर का घाटा हुआ था, जो जीडीपी का एक प्रतिशत था। मार्च तिमाही का आंकड़ा आने के साथ ही 2023-24 के समूचे वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा 23.2 अरब डॉलर पर आ गया, जो जीडीपी का 0.7 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश का चालू खाते का घाटा 67 अरब डॉलर यानी जीडीपी का दो प्रतिशत था।

11.4 अरब डॉलर का FPI इनफ्लो

वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में शुद्ध एफपीआई इनफ्लो 11.4 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले की समान अवधि में यह 1.7 अरब डॉलर का शुद्ध आउटफ्लो था। वित्त वर्ष 2023-24 में फोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में शुद्ध इनफ्लो 44.1 अरब डॉलर का रहा। एक साल पहले 5.2 अरब डॉलर का आउटफ्लो था। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध एफडीआई इनफ्लो 9.8 अरब डॉलर का रहा। एक साल पहले यह 28 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2023-24 में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 63.7 अरब डॉलर का इजाफा भी हुआ।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से सरकार की बंपर कमाई

21% बढ़कर 4,62,664 करोड़ रुपये पार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17 जून तक सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ है। केंद्रीय प्रत?यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह जानकारी दी है। डायरेक?ट टैक?स कलेक?शन सरकार के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन टैक?स का इस?तेमाल सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और विकास कार्यक्रमों को फंड करने के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष कर सरकार को आर्थिक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी धन मुहैया करते हैं।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 22.19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम टैक्स संग्रह 27.34 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाते हुए 1,48,823 करोड़ रुपये रहा। मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में कुल 53,322 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है।

आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.62 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें अग्रिम कर संग्रह में हुई बढ़ोतरी का विशेष योगदान रहा। अग्रिम कर की पहली किस्त 15 जून को देय थी। यह संग्रह 27.34 फीसदी बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपये रहा है। इसमें 1.14 लाख करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक?स (सीआईटी) और 34,470 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि 4,62,664 करोड़ रुपये (17 जून, 2024 तक) के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1,80,949 करोड़ रुपये का सीआईटी और 2,81,013 करोड़ रुपये का पीआईटी (प्रतिभूति लेनदेन कर सहित) शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने क्या रखा है टारगेट?

अप्रैल-जून के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (रिफंड के समायोजन से पहले) 5.16 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 4.23 लाख करोड़ रुपये था, जो 22.19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है। केंद्र ने इस वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह से 21.99 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है।

1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड सहित कई चीजों के बदल जाएंगे नियम, कतार में है ये डेडलाइन

नई दिल्ली। एजेंसी

क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम के अलावा, पेटीएम, एसबीआई कार्ड सहित कुछ बैंक भी अपनी तरफ से नए नियम तय करने वाले हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 20 जुलाई, 2024 को जीरो बैलेंस राशि वाले और पिछले वर्ष या उससे अधिक समय में कोई लेनदेन न करने वाले निष्क्रिय वॉलेट बंद कर देगा। साल 2024 के जुलाई महीने की शुरुआत होने में अब चंद रोज ही बाकी है। आगामी 1 जुलाई से वित्तीय क्षेत्र में कई सारे वित्तीय बदलाव होने वाले हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम के अलावा, पेटीएम, एसबीआई कार्ड सहित कुछ बैंक भी अपनी तरफ से नए नियम तय करने वाले हैं। ऐसे में जुलाई के करीब आते ही, आने वाली वित्तीय समय-सीमाओं और विनियामक परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है।

पेटीएम वॉलेट

पेटीएम पेमेंट्स बैंक 20 जुलाई, 2024 को जीरो बैलेंस राशि वाले और पिछले वर्ष या उससे अधिक समय में कोई लेनदेन न करने वाले निष्क्रिय वॉलेट बंद कर देगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, कृपया ध्यान दें कि वे सभी वॉलेट जिनमें पिछले 1 साल या उससे अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनमें शून्य शेष राशि है, 20 जुलाई, 2024 से बंद हो जाएंगे। सभी प्रभावित यूजर्स को कम्यूनिकेट किया जाएगा। यूजर्स को अपना वॉलेट बंद करने से पहले 30 दिनों की सूचना अवधि दी जाएगी।

एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड नियम

इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, एसबीआई कार्ड ने घोषणा की है कि 1 जुलाई, 2024 से कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए सरकारी संबंधित लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स को स्टोर करना बंद कर दिया जाएगा। एसबीआई कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, उन एसबीआई क्रेडिट कार्ड की लिस्ट जहां 15 जुलाई, 2024 से सरकारी संबंधित लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट लागू नहीं होंगे:

आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क

आईसीआईसीआई बैंक 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी विभिन्न क्रेडिट कार्ड सेवाओं में संशोधन की घोषणा की है। इसमें सभी कार्ड (एमराल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट को छोड़कर) पर कार्ड रिप्लेसमेंट फीस को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करना शामिल है।

ITR की समयसीमा

वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई, 2024 है। हालांकि सरकार विशेष परिस्थिति में तारीखों को आगे भी बढ़ाती है। अगर आप आप समयसीमा तक आईटीआर फाइल करने में विफल रहते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर, 2024 तक लेट फाइन के साथ लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

पीएनबी रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड

पंजाब नेशनल बैंक ने भी Rupay Platinum Debit Card के सभी वेरिएंट के लिए लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में संशोधन किया गया है। नए नियम 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे। इसमें प्रति तिमाही 1 (एक) घरेलू हवाई अड्डा/रेलवे लाउंज एक्सेस और प्रति वर्ष 2 (दो) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस शामिल हैं।

सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड

एक्सिस बैंक ने सिटीबैंक क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड खातों सहित सभी संबंधों को माइग्रेट करने के बारे में नोटिफाई किया, जो 15 जुलाई, 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

'पानी की कमी भारत की साख के लिए खतरा', मूडीज ने कहा- सामाजिक अशांति फैल सकती है

नई दिल्ली। एजेंसी

मूडीज रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा कि भारत में पानी की बढ़ती कमी भारत की साख के लिए खतरा है। मूडीज ने यह भी कहा कि पानी की कमी कृषि और उद्योग क्षेत्रों को बाधित कर सकती है।

भीषण गर्मी के बीच भारत में बढ़ता जल संकट देश की साख (कर्ज क्षमता) के लिए हानिकारक है। इस संकट के कारण न सिर्फ खाने- पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी बल्कि लोगों की आय में गिरावट भी आएगी। इन वजहों से देश में सामाजिक अशांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है। मूडीज रेटिंग्स ने मंगलवार को जारी 'भारत के समक्ष पर्यावरणीय जोखिम' रिपोर्ट में कहा, भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण दुनिया के सबसे अधिक ☐ आबादी वाले देश में पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। यह संकट ऋण क्षमता के लिहाज से उन क्षेत्रों के लिए भी हानिकारक है, जो पानी का भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे... कोयले से बिजली बनाने वाली कंपनियां और इस्पात निर्माता। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में जल संकट एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

और भी बदतर हो रहे हालात

रेटिंग एजेंसी ने कहा, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव तेजी से बढ़ने की वजह से जल संकट और भी बदतर हो रहा है। यानी भारत में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। इससे सूखा, लू और बाढ़ जैसी जलवायु संबंधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के अलावा तेज आर्थिक वृद्धि भी पानी की खपत को बढ़ा रही है।

1700 क्यूबिक मीटर से कम स्तर जल संकट को दर्शाता है

जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से मूडीज ने कहा, भारत की प्रति व्यक्ति औसत सालाना जल उपलब्धता 2031 तक घटकर 1,367 क्यूबिक मीटर रह जाने की आशंका है। यह 2021 में पहले से ही कम 1,486 क्यूबिक मीटर है। मंत्रालय के मुताबिक, 1,700 क्यूबिक मीटर से कम का स्तर जल संकट को दर्शाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी के मुताबिक, मानसूनी बारिश कम हो रही है। 1950-2020 के दौरान हिंद महासागर में प्रति शताब्दी 1.2 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ा है। 2020-2100 के दौरान यह बढ़कर 1.7-3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा।

समस्या से निपटने के उपाय जल प्रबंधन में निवेश जरूरी

मूडीज ने कहा, लंबी अवधि में जल प्रबंधन में निवेश के जरिये ही संभावित पानी की कमी से पैदा होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है। विश्व बैंक की फरवरी, 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने पिछले एक दशक में ग्रामीण समुदायों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन किया है। 1.2 अरब डॉलर की कुल फंडिंग वाली कई परियोजनाओं के जरिये दो करोड़ से अधिक लोगों को फायदा हुआ है।

1.8 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान

एसबीआई के अनुमान के मुताबिक, 2023 में उत्तर भारत में आई बाढ़ और गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय की वजह से बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ। इससे देश की अर्थव्यवस्था को 1.2-1.8 अरब डॉलर का झटका लगा।

दिखने लगा आत्मनिर्भर भारत का असर, चीन से आयात में आई कमी लेकिन अभी लंबा सफर है बाकी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। अब धीरे-धीरे इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। इस साल के पहले चार महीनों के दौरान चीन से आयात में कमी आई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च में चीन से आयात में गिरावट आई जबकि अप्रैल में यह सपाट रहा। हालांकि अब भी व्यापार संतुलन पूरी तरह चीन के पक्ष में है। यानी चीन से हम बहुत सारा सामान मंगाते हैं और चीन को उसकी तुलना में बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। अब भी हमारे कई सेक्टर पूरी तरह चीन से होने वाले आयात पर निर्भर हैं। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में चीन से आयात 8.96 अरब डॉलर रहा जो फरवरी में गिरकर 8.09 अरब डॉलर रह गया। मार्च में इसमें और गिरावट आई और यह 7.75 अरब डॉलर रहा। अप्रैल में यह

7.79 अरब डॉलर रहा। जनवरी-फरवरी के दौरान भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई जबकि इस दौरान ओवरऑल इम्पोर्ट में तेजी देखने को मिली। जनवरी में भारत का कुल आयात 53.35 अरब डॉलर रहा जिसमें चीन ही हिस्सेदारी 16.79 फीसदी रही। फरवरी में भारत का आयात बढ़कर 60.11 अरब डॉलर पहुंच गया लेकिन इसमें चीन की हिस्सेदारी 13.46 फीसदी रह गई। मार्च में भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 13.53 फीसदी और अप्रैल में 14.4 फीसदी रही।

चीन के साथ व्यापार घाटा

चीन से भारत टेलिकॉम और स्मार्टफोन पार्ट्स, लैपटॉप और पीसी, प्लास्टिक, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, नॉन-असेंबल्ड सेल, लीथियम-आयन बैटरी, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स शामिल हैं। चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत नॉन-एसेंशियल कंज्यूमर और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के आयात में कटौती के लिए काम कर रहा है। अप्रैल में चीन के बाद भारत के इम्पोर्ट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रूस (9.7 फीसदी) की रही। इसके बाद यूएई (6.14ः), अमेरिका (5.9ः) और सऊदी अरब (5.9ः) का नंबर है। रूस, यूएई और सऊदी अरब से भारत ज्यादातर कच्चा तेल मंगाता है।

व्हिस्की, ब्रांडी, वोदका, रम... दुनिया को लगा भारतीय शराब का चस्का, बाजार में आते ही मच रही लूट

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की शराब का नशा दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। ड्रिंक्स इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे 30 स्पिरिट ब्रांड्स में से एक तिहाई भारतीय हैं। इतना ही नहीं टॉप दस व्हिस्की ब्रांड्स में से छह भारत के हैं। भारत के कुल शराब मार्केट में दो-तिहाई के बराबर हिस्सेदारी व्हिस्की की है। व्हिस्की के साथ-साथ भारत के ब्रांडी, वोदका और रम ब्रांड्स को भी काफी पसंद किया जा रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और अगले पांच साल में 10 करोड़ लोग शराब पीने की लीगल एज में पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी शराब कंपनियां भारत पर फोकस कर रही हैं।'मिलियनेयर्स क्लब' की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ऐसे वर्ष में जब भारत आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया, इसने खुद को स्पिरिट्स की दुनिया में एक अग्रणी देश के रूप में भी स्थापित कर लिया। एक्साइज से जुड़े कुछ मुद्दे अब भी हैं जिनके कारण यहां बिजनस मुश्किल है।

लेकिन यह बात साल-दर-साल सच होती जा रही है कि यदि आप भारतीय बाजार को समझ पाए, तो संभावनाएं लगभग असीमित हैं। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स की आइकोनिक व्हाइट व्हिस्की ने 2023 में 1.6 मिलियन केस बेचे और 1500ः की बढ़ोतरी के साथ टॉप पर रही। लेकिन व्हिस्की ही नहीं है ब्रांडी, रम और वोदका ब्रांड भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रीज की कूरियर नेपोलियन और मैन्शन हाउस ब्रांडी, रेडिको खेतान की ब्रांडी मॉर्फियस, वोदका ब्रांड मैजिक मोमेंट्स और रम 1965 का प्रदर्शन शानदार रहा। यह इस बात का संकेत है कि भारतीय ग्राहक डाइवर्सिफाई हो रहे हैं।

भारतीय व्हिस्की का जलवा

तेजी से उभर रहे 10 ब्रांड्स में से छह में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई। आइकोनिक बनाने वाली कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का 1,500 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 जून को खुल रहा है। तिलकनगर इंडस्ट्रीज के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अहमद रहीमतुला ने कहा कि खासकर ब्रांडी कैटगरी में इनोवेशन और प्रीमियमीकरण की दिशा में हमारे प्रयासों को सफलता मिली है। हमारे ब्रांड हर साल मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज कर रहे हैं और हमें इसमें और तेजी आने का भरोसा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के मैकडॉवेल ने 2023 में सिर्फ 1.9ः ग्रोथ के बावजूद 31.4 मिलियन केस की बिक्री के साथ दुनिया के सबसे बड़े व्हिस्की ब्रांड का अपना टैग बरकरार रखा। वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के शीर्ष 30 व्हिस्की ब्रांड्स में से तेरह भारतीय हैं। इनमें रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू और ब्लेंडर्स प्राइड शामिल हैं। ये तीनों ब्रांड्स Pernod Ricard के हैं जबकि ऑफिसर्स चॉइस ब्रांड अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का है।

मोदी 3.0 के पहले बजट में रोबोट टैक्स!

निर्मला सीतारमण को एक्सपर्ट्स का प्रपोजल

नई दिल्ली। एजेंसी

अर्थशास्त्रियों ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इसमें उन्होंने आने वाले बजट पर चर्चा की। इस दौरान विकास, राजकोषीय नीति, निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर फोकस किया गया। साथ ही खाद्य महंगाई दर और कुल कर्ज को संभालने पर भी बात हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के रोजगार पर असर पर भी चर्चा हुई। विस्थापित श्रमिकों को फिर से कौशल प्रदान करने के लिए 'रोबोट टैक्स' के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। वित्त मंत्री के साथ हुई चर्चा में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया। इनमें निजी निवेश को बढ़ावा देने के उपाय, रोजगार सृजन, राजकोषीय समझदारी बनाए रखना के साथ कर्ज के स्तर और खाद्य महंगाई का प्रबंधन शामिल था। एक खास विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल और रोजगार पर इसके संभावित असर का था। एक अर्थशास्त्री ने 'रोबोट टैक्स' के विचार का सुझाव दिया। इस टैक्स से एआई-आधारित विस्थापन से प्रभावित वर्कर्स के पुनर्वास के लिए धन मिल सकता है।

IMF के पेपर में रोबोट टैक्स का जिक्र

'रोबोट टैक्स' की सिफारिश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक पेपर से मेल खाती है। पेपर में यह स्वीकार किया गया है कि एआई समग्र रूप से रोजगार और मजदूरी को बढ़ा सकता है। लेकिन, आईएमएफ ने लंबे समय में अहम नौकरियां जाने की आशंका के प्रति भी आगाह किया। इसने कहा कि यह बदलाव कई वर्कर्स के लिए दर्दनाक होगा। हालांकि, आईएमएफ के पेपर ने 'रोबोट टैक्स' को लागू करने के खिलाफ सलाह दी। लेकिन, इसने श्रम नीतियों और सामाजिक सुरक्षा तंत्रों का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत पर प्रकाश डाला।

आईएमएफ के पेपर में बेरोजगारी बीमा कवरेज के विस्तार और वेतन बीमा पर विचार करने के साथ कौशल और क्षेत्र-आधारित प्रशिक्षण पर अधिक फोकस करने का सुझाव दिया गया है। इसने यह भी सिफारिश की कि देश अपनी वर्तमान कॉर्पोरेट टैक्स प्रणालियों की समीक्षा करें कि वे ऑटोमेशन में निवेश को कैसे प्रोत्साहित करती हैं।

गीता गोपीनाथ ने चुनौतियों पर दिया था जोर

हाल ही में एक साक्षात्कार में आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने विकासशील देशों के लिए एआई की ओर से पेश की जाने वाली महत्वपूर्ण चुनौती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन देशों में अक्सर व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल का अभाव होता है।

उन्होंने कहा, 'अगर आप उन युवाओं के अनुपात को देखें जो न तो स्कूल में हैं, न ही काम कर रहे हैं या किसी भी तरह के प्रशिक्षण में हैं, तो यह संख्या उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक है। जिसका अर्थ है कि परिवर्तन से लाभ उठाने या परिवर्तन के अनुकूल होने की उनकी क्षमता और भी कठिन होने वाली है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकासशील देशों को एक मजबूत डिजिटल ढांचा, अधिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करने में अधिक निवेश करना होगा ताकि वे भी इस तकनीक से लाभान्वित हो सकें।' हालांकि यह पुष्टि नहीं हुई है कि आगामी बजट में एआई से संबंधित कदम शामिल किए जाएंगे या नहीं। लेकिन, आर्थिक सर्वे में इस तकनीक का उल्लेख किया जा सकता है, जो अगले महीने केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण की थमी रफ्तार, 6 महीने के लिए टल गया संचालन, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

अभी लोगों को नोएडा एयरपोर्ट से सफर करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एयरपोर्ट के निर्माण की रफ्तार थम गई है। अब इस एयरपोर्ट का संचालन 6 महीने के लिए टल गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) इस साल या अगले साल की पहली तिमाही में तो पूरा नहीं हो पाएगा। इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में अब कम से कम छह महीने की देरी हो गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने की तारीख को कम से कम छह महीने आगे बढ़ाकर अप्रैल 2025 कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि देरी की वजह टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में धीमी प्रगति है, जो तय समय से काफी पीछे चल रही है।हालांकि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) ने टर्मिनल के निर्माण में देरी के पीछे के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है। लेकिन मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि बिल्डिंग की छत के लिए जरूरी 'स्पेशल ग्रेड स्टील' का आयात अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमी के कारण प्रभावित हुआ है। एक बयान में वाईआईएपीएल ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि निर्माण की गति और अधिक प्रभावित न हो।

अभी करना होगा इतना इंतजार

बयान में कहा गया है, 'वर्तमान निर्माण स्थिति को देखते हुए, हम अप्रैल 2025 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की उम्मीद करते हैं। हम अपने ईपीसी ठेकेदार, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर निर्माण गतिविधियों की उच्च गति और परिचालन तत्परता की तैयारी बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं।' 31 मई को एक अनुमान के मुताबिक, पूरी परियोजना का 20३ से अधिक निर्माण अभी भी बाकी है। अधिकारियों ने कहा कि टर्मिनल भवन के लिए, अग्रभाग और वॉटरप्रूफिंग का काम चल रहा है।

स्टील की कमी पर चिंता

सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इस साल अप्रैल में टाटा प्रोजेक्ट्स ने स्टील की कमी के बारे में चिंता जताई थी। टाटा प्रोजेक्ट्स YIAPL की ओर से एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है, लेकिन कंपनी ने कंसेसियनार को यह भी आश्वासन दिया था कि वह कई विक्रेताओं से स्टील खरीदने की कोशिश कर रही है, ताकि निर्माण प्रभावित न हो। हालांकि, वाईआईएपीएल ने सहमति जताई कि अगले कुछ सप्ताह परियोजना की समयसीमा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हजारों कर्मचारी तैनात हैं

बयान में कहा गया है, 'यह एक बड़ी और जटिल परियोजना है और अगले कुछ सप्ताहों में निर्माण गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। रनवे, यात्री टर्मिनल और नियंत्रण टॉवर पर काम काफी आगे बढ़ चुका है। हाल ही में ग्राउंड हैंडलिंग, वाणिज्यिक क्षेत्रों के संचालन और महत्वपूर्ण रखरखाव अनुबंधों के लिए रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान कनेक्शन के लिए कई एयरलाइनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।'

फिलहाल, एयरपोर्ट साइट पर करीब 9,000 कर्मचारी तैनात हैं। एटीसी टावर पर कांच का मुखौटा लगभग पूरा हो चुका है। वहीं रनवे पर डामर की अंतिम परत चढ़ाई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि रनवे पर उड़ान से संबंधित उपकरणों की स्थापना भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ग्लाइड पाथ और लोकलाइजर जैसे महत्वपूर्ण नेविगेशन सहायक उपकरण स्थापित कर रहा है।

निर्माण में देरी पर नोटिस जारी

हवाई अड्डे का पहला चरण 1,334 हेक्टेयर में बनेगा और इसकी लागत 10,056 करोड़ रुपये आने की संभावना है। परियोजना के लिए यूपी सरकार के विशेष प्रयोजन वाहन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) ने कहा है कि वह देरी के लिए निर्माण कंपनी पर भारी जुर्माना लगाएगा। रियायत समझौते के मुताबिक, कंपनी को कुछ शर्तों के तहत 91 दिनों की छूट अवधि दी जाएगी। इसके बाद उस पर प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि वाईआईएपीएल को सोमवार को ही नोटिस जारी कर दिया गया था, क्योंकि उसने सरकारी निकाय से परामर्श किए बिना ही परियोजना पूरी करने की समयसीमा बढ़ा दी थी।

कंपनी पर लगेगा जुर्माना

एनआईएएल के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा, 'वाईआईएपीएल ने हमसे सलाह किए बिना समयसीमा बढ़ाने का एकतरफा फैसला किया। हम रियायत समझौते के अनुसार कंपनी पर जुर्माना लगाएंगे। हमने नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन रियायत अवधि के मामले पर राज्य सरकार फैसला करेगी।' मुख्य सचिव डीएस मिश्रा, जो एनआईएएल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं वह शुक्रवार को परियोजना समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन के अध्यक्ष रमन कपिल सहित टाटा प्रोजेक्ट्स के वरिष्ठ अधिकारी अपडेट के साथ तैयार रहेंगे।

इस बीच, एनआईएएल ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) से लेआउट अनुमोदन प्राप्त किए बिना रोज़ेट ग्रुप द्वारा एक होटल और एआईएसएटीएस द्वारा एक कार्गो टर्मिनल के निर्माण के बारे में भी आपत्ति जताई है। एनआईएएल ने नक्शे को मंजूरी देने की जिम्मेदारी वाईईआईडीए को सौंपी है क्योंकि उसके पास अपने स्वयं के उपनियम नहीं हैं।

नोएडा एयरपोर्ट में शुरू में एक रनवे और एक टर्मिनल होगा, जिसकी क्षमता सालाना 12 मिलियन यात्रियों को संभालने की होगी। इस परियोजना को चार चरणों में विकसित किया जाना है, जो अंततः दो रनवे और दो टर्मिनल भवनों तक विस्तारित होगी, और सालाना 70 मिलियन यात्रियों को समायोजित करेगी।

IGI एयरपोर्ट इस मामले में बना देश का पहला

लागू हुआ FTI-TTP, जानिए इस बारे में सबकुछ

नई दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अब इसके ताज में एक और हीरा लग गया। जी हां, यह एयरपोर्ट सरकार के 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम' (एफटीआई-टीटीपी) लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया। बताया जाता है कि इस सुविधा के शुरू होने से भारतीय पासपोर्ट धारकों और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारकों को बेहद आसानी हो जाएगी।

क्या है इसका उद्देश्य

आईजीआई एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (Delhi International Airport Limited (DIAL) का कहना है कि केंद्र सरकार का यह एक विजनरी इनीशिएटिव है। इसका उद्देश्य तेज, अधिक सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित आव्रजन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करके यात्रा अनुभव को बदलना है।

एफटीआई-टीटीपी क्या है और यह कैसे काम करता है?

एफटीआई-टीटीपी भारतीय नागरिकों और भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी पहल का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य गति, सरलता और बढ़ी हुई सुरक्षा पर जोर देते हुए यात्रा अनुभव को आधुनिक बनाना है।

कैसे मिलेगा इसका लाभ

इसका लाभ लेने के लिए भारतीय पासपोर्ट धारकों और ओसीआई कार्डधारकों को एक ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा और निर्दिष्ट विवरण के साथ बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट और चेहरे की छवि) जमा करना होगा। पात्रता के सत्यापन के बाद पंजीकरण को अंतिम रूप दिया जाएगा, और आवेदकों को सबमिशन प्रक्रिया के दौरान एफटीआई-टीटीपी के लिए लागू प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा।

एफटीआई पंजीकरण कैसे होगा

आवेदन प्रक्रिया एक गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान के साथ शुरू होती है, जिसके बाद आवेदक मोबाइल ओटीपी और ईमेल सत्यापन के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करना होगा। आवेदन में किसी भी तरह की हेराफेरी या महत्वपूर्ण विवरण छुपाए जाने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

इन आवेदकों का नहीं होगा पंजीकरण

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बायोमेट्रिक डेटा जमा करना अनिवार्य है। किसी तकनीकी कारण से बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ आवेदकों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, आवेदकों को भारत में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या निकटतम एफआरआरओ कार्यालय में बायोमेट्रिक कैप्चर के लिए नियुक्ति निर्धारित करने के लिए सूचित किया जाता है।

क्या है शुल्क

प्रसंस्करण शुल्क संरचना भारतीय नागरिकों के लिए ?2000, भारतीय नाबालिगों के लिए ?1000 और ओसीआई कार्डधारकों के लिए ञ100 है। इसके लिए आवश्यक अपलोड में एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर, पासपोर्ट के पहले और आखिरी पृष्ठ का फोटो या स्कैन, और प्रासंगिक दस्तावेज जैसे ओसीआई कार्ड (यदि लागू हो) और पते का प्रमाण शामिल हैं।

आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि में देवी को इन नौ भोगों से करें प्रसन्न, पूरी होंगी मनोकामनाएं

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का विशेष अवसर है. यह नवरात्रि साल में दो बार आती है, एक चैत्र मास में और दूसरी आषाढ़ मास में. इस साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि 1 जुलाई तक चलेगी. नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा के साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग लगाने की भी परंपरा है. माना जाता है कि देवी को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.आइए जानते हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि में देवी को लगाए जाने वाले नौ विशेष भोगों के बारे में:

✎ डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

कलशः नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है. इस दिन कलश को भोग लगाया जाता है. कलश में जल, दूध, गंगाजल, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, पान, लाल फूल आदि रखे जाते हैं.

फलः नवरात्रि के दूसरे दिन देवी को विभिन्न प्रकार के फल भोग लगाए जाते हैं. केला, सेब, संतरा, अंगूर, मौसमी फल आदि देवी को प्रिय हैं.

मिठाईः नवरात्रि के तीसरे दिन देवी को विभिन्न प्रकार की मिठाइयां भोग लगाई जाती हैं. खीर, हलवा, लड्डू, बर्फी, पेड़ा आदि देवी को प्रिय हैं.

पानः नवरात्रि के चौथे दिन देवी को पान का भोग लगाया जाता है. पान में सुपारी, लौंग, इलायची, कत्था आदि रखे जाते हैं.

दहीः नवरात्रि के पांचवें दिन देवी को दही का भोग लगाया जाता है. दही को चीनी और शहद के साथ मिलाकर भी लगाया जा सकता है.

घीः नवरात्रि के छठे दिन देवी को घी का भोग लगाया जाता है. घी को रोटी या चावल के साथ भी लगाया जा सकता है.

शहदः नवरात्रि के सातवें दिन देवी को शहद का भोग लगाया जाता है. शहद को दूध या पानी में मिलाकर भी लगाया जा सकता है.

नारियलः नवरात्रि के आठवें दिन देवी को नारियल का भोग लगाया जाता है. नारियल को फोड़कर उसका पानी और गूदा देवी को अर्पित किया जाता है.

तुलसीः नवरात्रि के नौवें दिन देवी को तुलसी का भोग लगाया जाता है. तुलसी के साथ ही अन्य ताजे हरे पत्ते भी देवी को अर्पित किए जाते हैं.

कुंडली में पितृ दोष कब और कैसे लगता है? जानें लक्षण के साथ किन-किन समस्याओं से जूझते ऐसे लोग

✎ पं. श्री रमेशचंद व्यास
(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषयाचार्य एवं
रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

पितृ दोष होता क्या है ? पितृ दोष यानी पित्रों का दोष होता है. पित्रों का दोष लगता कैसे है? यह विषय बड़ा है. हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि पितृ दोष कब और कैसे लगता है. ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब हमारे घरों में किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वह प्रेत बन के भटकता है. वहीं प्रेत अपनी मुक्ति के लिए जब हमे परेशान करता है तो उसे ही पितृ दोष कहते हैं.

अकाल मृत्यु होती क्या है?

अकाल मृत्यु का मतलब जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट या सुसाइड से मौत होना पर ही होता है. अकाल मृत्यु का मतलब है अककाल यानी काल से पहले. काल का मतलब होता है समय यानी समय से पहले जब किसी की मौत उसके निर्धारित समय से पहले हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं. आज के जीवन और आज के खान पान के अनुसार हर मनुष्य की लगभग 70 से 80 के बीच की उम्र ही पूरी उम्र मानी जाती है, जो व्यक्ति 50 या 55 साल के आस पास मरता है या इससे कम उम्र में उसे अकाल मृत्यु ही कहेंगे. लेकिन जो 50-55 के आस पास मरा और अपनी मौत से मरा होगा तो वो भी अकाल मृत्यु ही होगी. हालांकि मरने वाले का सही ढंग से क्रिया करम कर दिया जाए तो उसके मुक्ति का रास्ता बन जाता है. वहीं दूसरी अकाल मृत्यु वह होती है, जिनमें कोई एक्सीडेंट से मरा हो या सुसाइड किया हो तो ऐसी आत्मा का क्रिया करम करने से भी वो मुक्त नहीं होती है, उनके लिए अलग पूजन कराना पड़ता है.

घर में इस तरह भटकती हैं आत्माएं

इस तरह की आत्माएं घर में भटकती हैं. घर में भटकती आत्मा आपको परेशान करती है. जब आपके घर में प्रेत का वास होगा यानी आपके घर में जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ वो रहेगा तो अपने घर में ही न कहा जायेगा तो जब घर में प्रेत का वास हो जाए तो अपने आप बिना उनके परेशान किए ही आपके घर में परेशानी आने लगती है. क्योंकि घर में प्रेत का वास होता है जहां प्रेत रहते हैं वहा अपने आप नेगेटिविटी रहती है तो वहां किसी का काम कैसे बन सकता है तो इसी को पितृ दोष कहते हैं यानी पितरों का दोष जो अपनी उम्र पूरी कर के मरते हैं वह पितृ देव होते हैं. वह पूजनीय होते हैं. लेकिन जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह पितृ प्रेत होते हैं तो ऐसा जिनके घरों में यह समस्या है यानी पित्र प्रेत है या पितृ दोष लगा है, उनके घरों में कई प्रकार की दिक्कते आती हैं.

ज्यादातर लोगों के घर में बरकत नहीं होती है?

ज्यादातर लोगों के घर में बरकत नहीं होती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. ऐसे लोग आर्थिक समस्या से झूझते रहते हैं. विवाह में भी परेशानी आती हैं. किन्ही किन्ही के यहां ऐसा होता है की घर का आदमी कोई भी कार्य करता है और उसे सफलता नहीं मिलती है. काम अंत में सबकुछ खराब हो जाता है. किसी के यहां संतान होने में समस्या होती है या किन्ही के यहां संतान होती है तो सिर्फ लड़की होती है. वंश आगे नहीं बढ़ता और बार-बार आर्थिक झटके लगते हैं. संतान हानि होने लगती है. यह पितृ दोष के कुछ प्रमुख लक्षण हैं.

इस बार सावन में पांच सोमवार पर बन रहा है दुर्लभ योग, भक्तों को मिलेगी विशेष कृपा

✎ पंडित कपिल पाराशर
बनारस वाले ज्योतिष
आचार्य वास्तु विशेषज्ञ
6261493070

भगवान शिव के भक्तों के लिए इस बार का सावन मास विशेष फलदायी रहने वाला है. सावन मास की शुरुआत और समाप्ति सोमवार से होने जा रही है, जो एक दुर्लभ संयोग है. इसके अलावा, इस बार पांच सोमवार पड़ेंगे, जो भक्तों के लिए भगवान शिव की आराधना का एक अतिरिक्त अवसर लेकर आएगा.

विशेष योगों का समावेश

सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई को सोमवार से होगी और 19 अगस्त को सोमवार के दिन ही समाप्त होगा. इस पूरे मास में प्रीति योग और सावन नक्षत्र का समावेश रहेगा. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, इन शुभ योगों में भगवान शिव की पूजा-अर्चना और अभिषेक करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा बरसेगी.

पांच सोमवार का महत्व

सावन मास में पांच सोमवार का होना एक दुर्लभ घटना है. इस दौरान भक्त भगवान शिव की पूजा-अर्चन, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं. पांच सोमवार मिलने से भक्तों को भगवान शिव की आराधना का एक अतिरिक्त दिन मिल जाएगा, जिससे वे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना कर सकेंगे.

पिछले साल आठ सोमवार

पिछले साल सावन मास में आठ सोमवार पड़े थे, जो तीन साल में पड़ने वाले अधिमास के कारण हुआ था.

मंगला गौरी व्रत

सावन मास में अमूमन तीन मंगलवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार चार मंगलवार पड़ेंगे. इन दिनों श्रद्धालु मां मंगला गौरी का व्रत रखते हैं. जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही होती है, वह व्रत रखकर मां की पूजा करती हैं और मां को प्रिय हल्दी की माला चढ़ाती हैं.

पांच सोमवार, दुर्लभ योगों और मंगला गौरी व्रत के चार दिनों के साथ, यह सावन मास भक्तों के लिए विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है. भगवान शिव की आराधना और व्रत-अनुष्ठानों के माध्यम से भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने और भगवान की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे.

कुंडली में मौजूद केन्द्राधिपति दोष करियर को कर देता है बर्बाद, जानें लक्षण और अशुभ संकेत

✎ पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति के कुंडली में ग्रहों कि स्थिति और कुंडली में मौजूद दोष जानने के लिए नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय एवं जन्म स्थान के माध्यम से आंकलन किया जाता है. कुंडली में कोई भी दोष होना अच्छा नहीं माना जाता है. कहा जाता है कि जब कुंडली में ग्रह दोष लगता है तो व्यक्ति की जीवन नरकीय हो जाता है. जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष रहता है, ऐसे लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते है. जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, जो उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. जब कुंडली के भावों में शनि, राहु और मंगल स्थित होते हैं तो वे जातक की कुंडली को नुकसान पहुंचाते हैं. वहीं कुंडली में मौजूद शुभ ग्रहों के कारण बनने वाले दोष को केन्द्राधिपति दोष कहा जाता है. आइए जानते हैं कि यह दोष हमारी जन्म कुंडली को किस प्रकार प्रभावित करता हैष्ठ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी ग्रह को एक केन्द्र एवं एक मारक भाव का स्वामित्व प्राप्त हो तो उस ग्रह को केन्द्राधिपति दोष लगता है, जिसके विचारणीय पहलू निम्नवत है. केन्द्राधिपति दोष नैसर्गिक शुभ ग्रहों को लगता है, जिसमे सबसे अधिक दोष गुरु को, गुरु से कम शुक्र को, शुक्र से कम दोष बुध को बुध से कम दोष चन्द्रमा को लगता है. किसी जातक की कुंडली में इस दोष का निर्माण तब होता है जब बृहस्पति, शुक्र, बुध तथा शुक्ल पक्ष चंद्रमा जैसे लाभकारी ग्रह केंद्र भाव के स्वामी बन जाते हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक केंद्र भावों (पहले, चौथे, सातवें और दसवें भाव) के स्वामी तथा त्रिकोण भावों (पहले, पांचवें और नौवें भाव) के स्वामी हमेशा शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन इस दोष के प्रभाव में केंद्रों के स्वामी नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं.

कुंडली में अशुभ होता है केन्द्राधिपति दोष

देव गुरु बृहस्पतिः कुंडली में जब केंद्र भाव यानी कि पहले, चौथे, सातवें और दसवें भाव में बृहस्पति स्थित होते है तो केन्द्राधिपति दोष का निर्माण होता है. मिथुन और कन्या राशि पर बृहस्पति की स्थिति का प्रभाव अधिक होता है. मिथुन लग्न में गुरु को सप्तम एवं दशम का स्वामित्व के कारण केन्द्राधिपति दोष लगता है.

बुधः कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और दसवें भाव में जब बुध स्थित होते हैं, तो केन्द्राधिपति दोष लगता है. लेकिन पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसलिए यह दोष पहले भाव में नहीं होगा. लेकिन जब बुध, लग्न धनु राशि के चौथे भाव में हो तो शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती है. वहीं यदि बुध की महादशा चल रही हो और बुध सातवें भाव में स्थित है तो यह संबंधों को प्रभावित करेंगे. इसी प्रकार किसी जातक की कुंडली में बुध दसवें भाव में स्थित है, तो यह करियर में समस्याएं खड़ी करेंगे.

शुक्रः किसी जातक की कुंडली में शुक्र पहले, चौथे, सातवें और दसवें भाव में स्थित है तो केन्द्राधिपति दोष लगता है. मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न के लोग इस दोष से अधिक प्रभावित होते हैं. यदि किसी व्यक्ति पर शुक्र की महादशा चल रही है और उसका लग्न मेष हो और उसकी कुंडली में सातवें भाव में शुक्र बैठा हो तो उसे व्यवसाय और उनके संबंधों में दिक्कतें होती हैं.

गेहूं का दाम न बढ़े इसके लिए सरकार ने उठाया कदम, लगाई स्टॉक होल्डिंग लिमिट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

गेहूं के दाम न बढ़ें। इसकी जमाखोरी न हो और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यानी सोमवार को इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एकल खुदरा विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं और थोक व्यापारियों को हर शुक्रवार को अपने गेहूं स्टॉक की घोषणा करनी होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह देश में गेहूं की कमी की अफवाहों को दूर करना चाहते हैं। कहा कि अभी तक गेहूं के निर्यात पर कोई रोक नहीं है और चीनी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

इतनी होगी स्टॉक लिमिट

उन्होंने कहा, वह चाहते हैं कि गेहूं की कीमतें स्थिर रहें। आगे बताया कि थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन होगी, जबकि प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए यह उनकी प्रसंस्करण क्षमता का 70 प्रतिशत होगा। वहीं बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए यह प्रति दुकान 10 टन और कुल सीमा 3,000 टन होगी। वहीं एकल खुदरा विक्रेताओं के लिए यह 10 टन होगा।

इसलिए लिमिट लगाई गई

बताया कि हाल ही में मीडिया में आई खबरों के मद्देनजर स्टॉक सीमा लगाई गई है, जिन खबरों में गेहूं सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की बात कही जा रही है। उन्होंने बताया कि स्टॉक सीमा को जमाखोरी कम करने के लिए लगाया गया है। यह भी कहा कि खुदरा कीमतों पर नजर रखने के लिए कई उपकरण हैं और स्टॉक सीमा उन्हीं में से एक उपकरण है।

गेहूं की खरीद अभी जारी है

उन्होंने यह भी बताया कि 1 अप्रैल, 2023 को गेहूं का प्रारंभिक स्टॉक 82 लाख टन (एलएमटी) था, जबकि 1 अप्रैल, 2024 को यह 75 एलएमटी था। उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष 266 एलएमटी की खरीद की गई थी, जबकि इस वर्ष सरकार ने 262 एलएमटी की खरीद की है और खरीद अभी भी जारी है। इसलिए गेहूं की कमी (प्रारंभिक स्टॉक में) सिर्फ 3 लाख टन है।

आलू की पैदावार कम होने से नहीं भर सके कोल्ड स्टोर

एजेंसी

आलू की पैदावार कम होने से इस बार मेजारोड के कोहड़ार मार्ग स्थित शीतालय पूरी क्षमता से भरा नहीं जा सका। आलू पैदावार कम होने से आलू की कीमत दिनों दिन बढ़ रही है। आर बीएस शीतालय की देखरेख करने वाले प्रबंधक देवी प्रसाद सिंह ने बताया कि शीतालय की कुल क्षमता 86 हजार पांच सौ बोरी की है। इस बार 55 हजार दो सौ बोरी आलू का भंडारण किया गया, जिसमें छोटे किसानों से लेकर बड़े किसानों ने अपने आलू उत्पादन का अधिकांश हिस्सा आलू स्टोर में रखा है। किसान राम अचल पटेल निवासी बरहा कला मांडा ने बताया कि जिस समय आलू की खुदाई का समय आया उसी समय असमय बरसात के साथ ओले पड़ गए, जिससे किसानों के खेत में रहा पच्चास फीसदी आलू सड़ गया। किसानों को भारी चोट लगी। रोकड़ी करछना गांव के किसान दशरथ पटेल व संकठा प्रसाद ने बताया कि खेत का आपसी भाई बंटवारा होने से अब छोटे किसानों ने आलू की बुआई करना छोड़ अन्य फसलों की बुआई करने में जुट गया है। जिससे आलू बुआई का क्षेत्र दिनों दिन कम होता जा रहा है। एक दशक पहले यमुनापार में आलू भंडारण के लिए मेजा, करछना सहित अन्य स्थानों पर कई शीतगृह बनाए गए थे, आलू का उत्पादन कम होने से शीतगृह अपनी क्षमता के अनुसार भर नहीं पाते थे, शीतगृहों के संचालक फायदे के स्थान पर घाटा उठाते रहे, जिससे आलू स्टोर मालिकों ने शीतगृह के स्थान पर दूसरा कारोबार चुन लिया। सब्जी का राजा कहा जाने वाला आलू का दाम दिनों दिन बढ़ रहा है, माह भर पहले 18 सौ रूपए प्रति क्विंटल में बिकने वाला आलू इस समय 22 सौ रूपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। आलू बुआई के समय रेट और अधिक बढ़ने की संभावना है। कई बड़े व्यापारी स्थानीय स्तर पर आलू का भाव टाइट देख फरूखाबाद सहित अन्य जनपदों से आलू मंगवाकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं।

मिर्ची की खेती करने वाले किसानों को धानुका की नई तकनीकी सौगात

✍राम एस. पाल

खरगोन। भारत की अग्रणी कृषि-इनपुट कंपनी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने मिर्ची के किसानों के लिए अपने नए उत्पाद 'लानेवो' का विक्रेता लॉन्च किया। इस सफल कार्यक्रम में 95 विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। लानेवो को जापान की निसान केमिकल कॉर्पोरेशन के साथ रणनीतिक सहयोग के अंतर्गत तैयार किया गया है, जिसने धानुका के कीटनाशक पोर्टफोलियो को और भी मजबूत किया है। लानेवो अपनी अनूठी क्रियाविधि से चूसने और चबाने वाले दोनों तरह के कीटों के खिलाफ उन्नत फसल सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे किसानों को दोहरा लाभ मिलता है। इस अवसर पर धानुका टीम ने अपने प्रमुख उत्पादों और तकनीकों की जानकारी दी।

मिर्ची की खेती के विशेषज्ञ श्री महेश कुमार शर्मा ने मिर्ची फसल के लिए लानेवो उत्पाद के उपयोग की विधि और लाभों के बारे में विस्तार से बताया।

इससे पहले धानुका एग्रीटेक के डीजीएम-सेल्स श्री अखिल शर्मा ने इंडिया का प्रणाम और धानुका कंपनी का परिचय प्रस्तुत किया, जिसमें कंपनी के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं, धानुका एग्रीटेक के डीजीएम-मार्केटिंगः क्रॉप बिजनेस मैनेजर श्री सुबोध कुमार गुप्ता ने मिर्ची फसल में 'डिसाइड' (अम्ग्) उत्पाद के लाभ और उपयोग की जानकारी साझा की, और श्री निखिल मालवीय ने 'माईकोर सुपर' (श्भ्ण्धिं एल्जी) के बारे में बताया, जो मिट्टी के स्वास्थ्य और जड़ों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस कार्यक्रम में मनीष ट्रेडर्स और श्री कृष्णा एग्रीटेक के विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए, जिन्होंने धानुका के साथ अपने अनुभव और सफलता की कहानियों को साझा किया। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का उद्देश्य है कि वह अपने नवीनतम और प्रभावी उत्पादों के माध्यम से किसानों की उपज और आय में सुधार करे। इस कार्यक्रम के माध्यम से कंपनी ने मिर्ची किसानों को नई तकनीकी और उत्पादों के प्रति जागरूक किया और उनके खेती के अनुभव को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया।

चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट

करीब 2 हजार रुपये सस्ती, जानें आज क्या है सोने का भाव

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 26 जून, 2024 को सोना और चांदी सस्ता हुआ है। सस्ता होने के बाद सोने की कीमत 71 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के

पार है। वहीं, चांदी का भाव 86 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 71252 है. जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी (एग्नी) की कीमत 86570 रुपये है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 71739 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो सुबह 71252 रुपये पर आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं।

आज क्या है सोने-चांदी की कीमत

आधिकारिक वेबसाइट ग्रैंी.म्दर के मुताबिक, सुबह 995 प्योरिटी वाले दस ग्राम सोने के दाम घटकर 70967 रुपये पहुंच गए हैं। वहीं, 916 (22 कैरेट) प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 65267 रुपये का हो गया है। इसके अलावा, 750 प्योरिटी वाले (18) कैरेट) सोने के दाम 53439 पर आ गए हैं। वहीं, 585 प्योरिटी वाला गोल्ड (14 कैरेट) सस्ता होकर 41682 रुपये में आ गया है। इसके अलावा, 999 प्योरिटी वाली एक किलो चांदी आज 86570 रुपये की हो गई है।

मिस्ड कॉल से जानिए सोने-चांदी का भाव

ग्रैं की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं। 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के खुदरा रेट जानने के लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपडेट्स की जानकारी के लिए www.ibja.co या ibjarates.com पर देख सकते हैं।

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टेंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं। IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं।

भारत नहीं भूला कारगिल, हथियार देकर चुका रहा अहसान

इजरायल के पूर्व राजदूत ने हिंदुस्तान की जमकर तारीफ की

तेल अवीव। एजेंसी

भारत में इजरायल के राजदूत रह चुके डैनियल कार्मन ने गाजा युद्ध में उलझे उनके देश को इंडिया से हथियार मिलने के लिए तारीफ की है। इजरायली मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इजरायली सहायता के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए इजरायल को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। 2014 से 2018 तक भारत में इजरायल के राजदूत रहे डैनियल की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब लगातार ऐसी खबरें आई हैं कि भारत ने इजरायल को ड्रोन और तोपखाने के गोलों की आपूर्ति की है क्योंकि हमास के खिलाफ आठ महीने से अधिक समय से जारी युद्ध के चलते इजरायल के पास हथियारों की कमी हो गई है।

डैनियल कार्मन भ्हाूहौ को दिए साक्षात्कार में कहा, 'भारतीय हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान इजरायल उनके साथ था। इजरायल उन कुछ देशों में से एक था जो उनके साथ खड़ा था और उन्हें हथियार मुहैया कराता था। भारतीय इसे नहीं भूलते हैं और अब वे इसका बदला चुका सकते हैं।' भारत ने अब तक इजरायल को हथियारों की आपूर्ति की न तो पुष्टि की है और न ही इनकार किया है। भारत की ओर से कहा गया है कि वह गाजा में संघर्ष का बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। हालांकि मई में स्पेन ने अपनी बंदरगाहों पर भारत से इजरायल के लिए हथियार ले जाने वाले जहाजों को रुकने अनुमति देने से इनकार किया था। इससे पता चला था कि भारत की ओर से इजरायल को मदद की जा रही है।

कारगिल युद्ध में कैसे की थी इजरायल ने मदद

डैनियल कार्मन ने साल 1999 में मई और जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई का जिक्र किया था। भारत को उस वक्त इजरायल से गाइडेड युद्ध सामग्री और निगरानी टूल समेत महत्वपूर्ण सैन्य आपूर्ति, ड्रोन और उपकरण मिले थे। इनसे भारतीय सेना को युद्ध के मैदान में काफी मदद मिली थी।

कारगिल की लड़ाई तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तानी फौज के जवान द्रास सेक्टर में घुस आए थे। पाकिस्तानी सैनिकों के ऊंचाई पर होने की वजह से भारत के सामने मुश्किल आ रही थी। ऐसे वक्त में इजरायल आर्मी की ओर से मिली काउंटर टेररिज्म और लिमिटेड वॉर की जानकारी भारतीय सेना के काम आई थी। इजरायल ने भारत को ऊंचाई पर निगरानी करने वाले हेरान और सर्चर जैसे यूएवी भी दिए। इससे इंडियन आर्मी को घुसपैठियों की सटीक लोकेशन हासिल करने में मदद मिली। इसी मदद का हवाला देते हुए अब इजरायल के पूर्व राजनयिक भारत के अहसान उतारने की बात कह रहे हैं।

ग्रेट लर्निंग की अपस्किलिंग ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार

85% भारतीय प्रोफेशनल्स वित्त वर्ष 2025 में अपस्किलिंग में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं

आईपीटी नेटवर्क

उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख विश्वव्यापी ाुम्प फर्म ग्रेट लर्निंग ने 'अपस्किलिंग ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024-25' का तीसरा संस्करण प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में पिछले वर्ष के दौरान भारत में ग्रेट लर्निंग के कार्यक्रमों में देखे गए रुझानों का सार दिया गया है। इसके अलावा, एक शोध फर्म के सहयोग से, ग्रेट लर्निंग ने विभिन्न उद्योगों के 1000 से अधिक पेशेवरों के साथ एक व्यापक सर्वेक्षण किया, ताकि आगामी वर्षों में भारतीय पेशेवरों की अपस्किलिंग इच्छाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण रुझानों और चर की पहचान की जा सके। इस शोध का उद्देश्य पेशेवरों और व्यवसायों को यह समझने में मदद करना है कि ये रुझान व्यवसायों को कैसे प्रभावित करेंगे, आवश्यक कौशल का पूर्वानुमान लगाएंगे और प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए खुद को तैयार करेंगे। 79% प्रोफेशनल्स वित्त वर्ष 25 में अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कौशल उन्नयन को महत्वपूर्ण मानते हैं।

वित्त वर्ष 2025 में, पूछे गए 79% पेशेवरों का मानना था कि अपने पेशे को भविष्य के लिए बेहतर बनाने के लिए अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है। 17 वर्ष से अधिक अनुभव वाले 92% प्रोफेशनल्स अपस्किलिंग को महत्वपूर्ण मानते हैं। 17 वर्ष से अधिक अनुभव वाले 92% प्रोफेशनल्स अपस्किलिंग को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अतिरिक्त, इंजीनियरिंग डिग्री वाले प्रोफेशनल्स और घ्ऊ/ऊातम्दस/ऊाम्प सेक्टर में काम करने वाले लोग भी मानते हैं कि अपस्किलिंग ज़रूरी है। ऐसा संभवतः इसलिए हो सकता है क्योंकि नौकरी की सबसे हालिया रिपोर्ट के अनुसार, IT क्षेत्र में हायरिंग में 16% कम हुई है। प्रौद्योगिकी व्यवधानों और बदलते बाजार की गतिशीलता के परिणामस्वरूप भारत में उद्योगों में तेजी से बदलाव हो रहा है, इसलिए नियोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोफेशनल्स लोग अतिरिक्त विशेषज्ञ कौशल सीखने की आवश्यकता के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं। तकनीकी व्यवधानों और व्यापक आर्थिक स्थितियों के बीच भारतीय प्रोफेशनल्स में नौकरी बनाए रखने के आत्मविश्वास 62% तक कमी आयी है। भारतीय पेशेवरों में अपनी नौकरी बनाए रखने के प्रति विश्वास में पिछले वर्ष की तुलना में नौ प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट आई है। पिछले वर्ष के सर्वेक्षण में, 71% पेशेवरों को नौकरी बनाए रखने पर भरोसा व्यक्त किया था, लेकिन इस साल यह अनुपात घटकर 62% रह गया है। यह भावना दुनिया भर में आर्थिक कठिनाइयों और नौकरियों में किये गए। छंटनी से संबंधित हो सकती है। केवल 29% प्रवेश स्तर के प्रोफेशनल्स ही अपनी नौकरी बनाए रखने के प्रति आश्वस्त हैं। विभिन्न उद्योगों का डेटा भी इस बात का समर्थन करता है। मार्च 2024 में, नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स, इंडेक्स के मुताबिक, सिर्फ 2657 व्हाइट कॉलर नौकरी के अवसर थे जो कि पिछले वर्ष मार्च की तुलना में 11% कम है। वित्त वर्ष 2025 में 85% प्रोफेशनल्स कौशल बढ़ाने की योजना बना रहे हैं; बैंगलोर और चेन्नई में काम करने वाले पेशेवरों का सबसे अधिक कौशल विकास में निवेश करने की योजना बना रहे हैं।

ओला ने इलेक्ट्रिक रश ऑफरों की घोषणा की

बैंगलुरू। आईपीटी नेटवर्क

ओला इलेक्ट्रिक अपने 'ओला इलेक्ट्रिक रश' अभियान के अंतर्गत अपने एस1 पोर्टफोलियो पर 15,000 रुपये तक के आकर्षक ऑफर प्रदान कर रहा है। 28 जून तक लागू इन ऑफरों में एस1 एक्स पर 5,000 रुपये और एस1 प्रो एवं एस1 एयर पर 2,500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्राहकों को 10,000 रुपये तक के अतिरिक्त फायदे प्रदान किए जा रहे हैं, जिनके अंतर्गत एस1 एक्स पर 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और एस1 के संपूर्ण पोर्टफोलियो पर चुनिंदा क्रेडिट कार्ड ईएमआई के साथ 5,000 रुपये तक का कैशबैक शामिल है।

ओला इलेक्ट्रिक एक विशाल एस1 पोर्टफोलियो पेश करता है, जिसमें आकर्षक मूल्य में छः उत्पाद हैं, जो विभिन्न रेंज की जरूरत वाले ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। हाल ही में कंपनी ने मास-मार्केट सेगमेंट में अपना एस1 एक्स पोर्टफोलियो उतारा है। तीन बैटरी कॉन्फिगुरेशन (2 किलोवॉटघंटा, 3 किलोवॉटघंटा, और 4 किलोवॉटघंटा) के साथ इन स्कूटरों का मूल्य क्रमशः 74,999 रुपयेय 84,999 रुपये और 99,999 रुपये है। साथ ही इसके प्रीमियम स्कूटरों में एस1 प्रो, एस1 एयर, और एस1 एक्स का मूल्य क्रमशः 1,29,999 रुपये, 1,04,999 रुपये और 89,999 रुपये है। ओला इलेक्ट्रिक अपने उत्पादों की संपूर्ण श्रृंखला पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के 8 साल 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड बैटरी वॉरंटी प्रदान करता है। ओला इलेक्ट्रिक का मानना है कि इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की उम्र बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में आने वाली एक बड़ी बाधा का समाधान हो सकेगा। ग्राहक एड-ऑन वॉरंटी लेकर 1,00,000 किलोमीटर तक की दूरी को केवल 4,999 रुपये देकर और 1,25,000 किलोमीटर तक की दूरी को केवल 12,999 रुपये देकर वॉरंटी के अंतर्गत ला सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने 3 किलोवॉट की एक पोर्टेबल फास्ट चार्जर एक्सेसरी भी पेश की है, जो 29,999 रुपये में खरीदी जा सकती है।

5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सिर्फ 7 राउंड में खत्म, सरकार ने जुटाए 11,300 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की दूसरी 5उ स्पेक्ट्रम नीलामी सात राउंड के बाद बुधवार दोपहर को सात राउंड में खत्म हो गई है। यह नीलामी एक दिन से थोड़ा ज़्यादा समय तक चली। इससे सरकार ने करीब 11,300 करोड़ रुपये मिले हैं। बताया जा रहा है कि भारती एयरटेल इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी है। इसने कम खर्च वाले सब-गीगाहट्र्ज 900 मेगाहट्र्ज बैंड के साथ-साथ 1800 और 2100 मेगाहट्र्ज बैंड में भी स्पेक्ट्रम खरीदा है। वहीं मार्केट लीडर रिलायंस जियो ने 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 5उ बैंडविड्थ खरीदी है, जबकि वोडाफोन आइडिया (न्र) ने संभवतः 900/1800/2500 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदा है।

एयरटेल ने अपनाई ये रणनीति

एयरटेल और न्र ने बड़े पैमाने पर उन टेलीकॉम सर्किल में स्पेक्ट्रम खरीदने की अपेक्षित रणनीति अपनाई है, जहां उनके परमिट इस साल समाप्त हो रहे हैं। इस साल की नीलामी में सरकार ने 10.5 गीगाहट्र्ज 5जी एयरवेव्स की पेशकश की, जिसकी कीमत आरक्षित मूल्य पर 96,238.45 करोड़ रुपये थी। सरकार के लिए अंतिम राजस्व संग्रह जुलाई 2022 में 5जी एयरवेव्स की बिक्री में एकत्र किए गए रिकॉर्ड 1,50,173 करोड़ रुपये से काफी कम था और मार्च 2021 की 4जी नीलामी में एकत्र किए गए 77,814 करोड़ रुपये से भी कम था।

मेटा एआई का भारत में आगमन प्रमुख एआई असिस्टेंट अब आपके फोन पर उपलब्ध

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मेटा एआई को मेटा Llama 3 के साथ बनाया गया है और यह दुनिया के सबसे अग्रणी एआई असिस्टेंट्स में से एक है। यह 12 से ज़्यादा देशों में लोगों के फोन में पहले ही मुफ्त में उपलब्ध है। और अब इसे भारत में अंग्रेज़ी में रोल किया जा रहा है। आप मेटा एआई का उपयोग व्हॉट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पर चीज़ें करवाने, कंटेंट निर्माण करने और आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ों से जुड़े रहने के लिए कर सकते हैं। हमने पहली बार मेटा एआई की घोषणा पिछले साल के कनेक्ट में की थी और अप्रैल से दुनियाभर के लोगों के लिए हम Llama 3 से बने मेटा एआई का सबसे लेटेस्ट वर्जन लेकर आ रहे हैं।

मेटा एआई को आपके लिए उपयोगी बनाइए

क्या आप दोस्तों के साथ रात को बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं? आपके व्हॉट्सऐप ग्रुप चैट मैं ज़बरदस्त रिव्यू वाले और वीगन विकल्पों वाले रेस्टॉरेंट रिकमेंड करने के लिए कहें जहां आप और आपके दोस्त जा सकते हैं। क्या आप वीकएंड पर कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं? मेटा आई से रोड ट्रिप के दौरान ठहरने की जगहों के बारे में आपको आइडिया देने के लिए कहें। क्या आप किसी परीक्षा के लिए याद कर रहे हैं? वेब पर मेटा एआई को अनेक विकल्पों वालीएक परीक्षा तैयार करने के लिए कहें। क्या आप अपने खरीदे हुए पहले अपार्टमेंट में शिफ्ट होने जा रहे हैं? मेटा एआई से आप जैसी खूबसूरती चाहते हैं उसे 'ईमेजिन' करने के लिए कहें ताकि आप फर्नीचर शॉपिंग के लिए एआई जनरेटेड इमेजेस का एक मूड बोर्ड तैयार कर सकें।

फीड में मेटा एआई

जब आप अपने फेसबुक फीड को स्क्रोल कर रहे हों, तब भी आप मेटा एआईएक्सेस कर सकते हैं। क्या आपको कोई ऐसी पोस्ट देखने को मिली है जिसमें आपकी दिलचस्पी है? आप पोस्ट से ही मेटा एआई को अधिक जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। तो यदि आपने आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स की एक फोटो देखी है, तो आप मेटा एआई से पूछ सकते हैं के औरोरा बोरियलिस यानी उत्तर ध्रुवीय ज्योति देखने का साल का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है।

Yes Bank ने रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक ने कॉस्ट कटिंग की 500 कर्मचारियों को निकाला

नई दिल्ली। एजेंसी

प्राइवेट सेक्टर के बैंक, Yes Bank ने अपने 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बैंक के जुड़े सूत्रों से यह जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार, बैंक ने रिस्ट्रक्चरिंग की कवायद के तहत यह कदम उठाय है। बैंक में आगे और छंटनी की आशंका है। मिली जानकारी के अनुसार, बैंक ने अपने सभी वर्टिल से कर्मचारियों को निकाला है। निकाले गए लोगों को तीन महीने के वेतन के बराबर भत्ता दिया गया है। बैंक से छंटनी की खबर आने का शेयर पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। 12.30 तक शेयर 0.17% गिरकर 23.98 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

डिजिटल बैंकिंग के जरिये लगात घटाने की तैयारी

जानकारों का कहना है कि बैंक डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल बढ़ाकर अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने की कवायद कर रहा है। आपको बता दें कि बैंक के ऑपरेशनल कॉस्ट में पिछले वित्त वर्ष में लगभग 17इ की वृद्धि हुई थी। यह कदम ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने की दिशा में देखा जा रहा है। बैंक, जिसका सबसे बड़ा शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है, परिचालन लाभ को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वित्त वर्ष 24 के अंत में, यस बैंक का परिचालन लाभ एक साल पहले के 3183 करोड़ रुपये के मुकाबले 6.4% बढ़कर 3386 करोड़ रुपये था।

कर्मचारियों पर बैंक का बढ़ा खर्च

वित्त वर्ष 2024 और 2023 के बीच बैंक का कर्मचारियों के मद में खर्च 12% से अधिक बढ़ गया। बैंक ने वित्त वर्ष 24 के अंत में कर्मचारियों पर 3774 करोड़ रुपये खर्च किए। वहीं, वित्त वर्ष 23 के अंत में कर्मचारियों पर 3363 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। वित्त वर्ष 24 के अंत में बैंक के पास लगभग 28,000 कर्मचारी थे। एक साल में 484 लोगों की नियुक्ति हुई। कुल कर्मचारियों में से 23,000 से अधिक कर्मचारी जूनियर प्रबंधन श्रेणी के हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।